

प्रेषक,

एन०एस०नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व विभाग

देहरादून: दिनांक ०५ जुलाई, २००८

विषय:- वी०आर०डी०फार्मास्यूटिकल को फार्मास्यूटिकल उद्योग की स्थापना हेतु तहसील रूडकी के ग्राम माधोपुर, हजरतपुर में कुल ०.३०५० है० भूमि कय करने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं०- १३३९/भूमि व्यवस्था, दिनांक ५-१२-२००६ के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वी०आर०डी०फार्मास्यूटिकल को फार्मास्यूटिकल उद्योग की स्थापना हेतु उत्तरांचल(उ०प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५०) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, २००१) (संशोधन) अधिनियम, २००३ दिनांक १५-१-२००४ की धारा- १५४(४)(३)(क)(V) के अन्तर्गत तहसील रूडकी के ग्राम माधोपुर, हजरतपुर में कुल ०.३०५० है० भूमि खसरा न० - ८० का रकबा ०.०१५० है०को छोड़कर जिसमें नाली दर्ज है, शेष क्षेत्रफल ०.३०५० है० पर वी०आर०डी०फार्मास्यूटिकल को फार्मास्यूटिकल उद्योग की स्थापना हेतु तहसील रूडकी के ग्राम माधोपुर हजरतपुर जनपद हरिद्वार में भूमि कय करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं।

१- क्रेता धारा-१२९-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।

२- क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-१२९ के अन्तर्गत भूमिधरी से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

.....(२)

- 3- क्रेता द्वारा कय की गयी भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गयी है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।
- 4- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि कय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।
- 5- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।
- 6- शासन द्वारा दी गई भूमि कय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी। उक्त अवधि में निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना होगा एवं दो वर्ष के भीतर योजना का निर्माण कार्य पूरा करना होगा।
- 7- जिन व्यक्तियों द्वारा बैंक से ऋण लिये गये हैं उन्हें संबंधित बैंक से अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 8- फार्मास्यूटिकल उद्योग का निर्माण कार्य राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा) के अन्तर्गत जी0आई0डी0सी0आर0-2005 में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगा।
- 9- कय की जाने वाली भूमि का भू-उपयोग नियमानुसार औद्योगिक में परिवर्तित कराकर निर्धारित नीति/मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत प्रचलित नियमों/मानकों एवं भवन उपविधियों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए औद्योगिक प्रयोजन हेतु भवन निर्माण का प्लान सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराने के पश्चात ही प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- 10- प्रस्तावित उद्योग का निर्माण कार्य सीडा से ले आउट स्वीकृत कराने के पश्चात प्रारम्भ किया जायेगा।
- 11- प्रस्तावित उद्योग में स्थापित होने वाली औद्योगिक ईकाइयों में प्रदेश के स्थानीय निवासियों को 70 प्रतिशत से अधिक रोजगार/सेवायोजन उपलब्ध कराया जायेगा।

12- इकाई द्वारा कय की जाने वाली भूमि का उपयोग मात्र प्रस्तुत प्रोजैक्ट रिपोर्ट में उल्लिखित प्रस्तावित कम्पनियों के औद्योगिक प्रयोजन से सम्बन्धित किया कलापों की स्थापना हेतु ही किया जायेगा। प्रस्तावित ईकाई को स्वयं के संसाधनों से अवस्थापना सुविधाओं का विकास करना होगा।

13- प्रश्नगत उद्योग की स्थापना के सम्बन्ध में स्पॉट जोनिंग क्षेत्र के लिए निश्चित सिद्धान्त/नीतियों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

14- इकाई में पूंजी निवेश से पूर्व प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड तथा अग्निशमन विभाग आदि विभागों से नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

15- प्रश्नगत उद्योग की स्थापना के सम्बन्ध में अनापत्ति मात्र भूमि कय व्यवस्था के सन्दर्भ में दी जा रही है। केन्द्रीय औद्योगिक पैकेज के अन्तर्गत देय सुविधाओं/छूट हेतु इकाई की अर्हता स्वतः निर्धारित नहीं करती है, जो इकाई की स्थापना के पश्चात आवेदन करने पर सुसंगत नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

16- अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त प्रस्तावित भूमि का विक्रय/अन्तरण अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी स्थिति में विक्रय के लिये सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

17- भूमि के कय के तत्काल उपरान्त उसका सीमांकन कर लिया जायेगा जिससे अन्य किसी निजी सरकारी या सार्वजनिक भूमि के उपयोग की संभावना न रहे।

18- इकाई की स्थापना व संचालन के लिये वाछित सभी विधिक व अन्य प्रमाण पत्र/अनापत्ति पत्र या अनुज्ञायें नियमानुसार प्राप्त कर ली जायेंगी।

19- उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

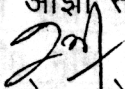
(एन0एस0नपलच्याल)

प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून
- 2- प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 4- श्री जोगेन्द्र कुमार वैद्य, पार्टनर, वी0आर0डी0 फार्मास्यूटिकल्स सी/ओ, प्लॉट न0-25-26, सैक्टर 2 औद्योगिक क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, हरियाणा ।
- 5- निदेशक एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 6- प्रभारी मीडिया सेन्टर उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सतोष बडोनी)
अनुसचिव।